

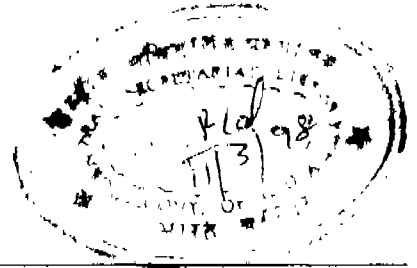


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 16 ]  
No. 16 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 1998/पौष 18, 1919  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 1998/PAUSA 18, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

( विधायी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1998

क्रा. आ. 29 ( अ ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1997 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, 24 नवम्बर, 1997 को दिये गये आदेश को प्रकाशित करती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय में

प्रारम्भिक अधिकारिता

राष्ट्रपतीय निर्वाचन अर्जी सं. 1/1997

श्री चरण लाल साहू और एक अन्य .....अर्जीदार

बनाम

श्री के. आर. नारायणन और एक अन्य .....प्रत्यर्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल :—

यह निर्वाचन अर्जी दो अर्जीदारों अर्थात् चरण लाल साहू और मिथिलेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फाइल की गई है। उन्होंने निर्वाचन में भारत के राष्ट्रपति के पद पर प्रत्यर्थी संख्या-1 के निर्वाचन को चुनौती दी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर श्री एस. गोपालन, महासचिव लोकसभा द्वारा प्रकाशित अधिसूचना तारीख 9 जून, 1997 के अनुसरण में कराया गया था। उक्त निर्वाचन राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है ) के उपबंधों के अधीन आयोजित किया गया था।

2. अधिनियम के भाग-2 ( धारा 3 से 12 ) में राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन के संचालन विषयक उपबंध हैं। धारा 3 निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 4(1) निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना

जारी करने के लिये उपबंध करती है जिसमें नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख नाम निर्देशनों की समीक्षा की तारीख, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख, वह तारीख जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो तो होगा, विहित की जाएगी। धारा 5, धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन की लोक सूचना देने के लिए उपबंध करती है। धारा 5क में विहित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए संविधान के अधीन उस पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा। धारा 5ख नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती है और विधिमाम्य नाम निर्देशन के लिए अपेक्षाएं अधिकथित करती है। धारा 5ख की उप-धारा (1) द्वारा यह अपेक्षित है कि विहित प्रारूप में भरा गया नाम निर्देशन पत्र नाम निर्देशन की अनुमति देते हुए अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उप-धारा (1) के खंड (क) में, जिस रूप में यह 5 जून, 1997 से पूर्व था, यह भी विहित किया गया था कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दिशा में कम-से-कम 10 निर्वाचकों के प्रतिस्थापकों के रूप में और कम-से-कम 10 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर होंगे। धारा 5ख की उपधारा 2 में अधिकथित है कि प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी। ऐसा नाम निर्देशन पत्र, जिसके साथ ऐसी प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है धारा 5ख की उप-धारा (4) के अधीन नामजूर कर दिया जाएगा। 5 जून, 1997 से पहले धारा 5क द्वारा विहित किया गया था कि किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक्तः नाम निर्देशित नहीं समझा जाएगा जब तक वह दो हजार पांच सौ रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है। धारा 5ख नाम निर्देशनों की समीक्षा के लिए उपबंध करती है और धारा (3) के अधीन नाम निर्देशन पत्र इसकी आधार (क) से (ड) पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा यह मंजूर किया जा सकता है। आधार (ग) इस आधार पर नाम निर्देशन पत्र को नामजुरी के लिए उपबंध करता है कि उस पर अपेक्षित संख्या में प्रस्थापकों या समर्थकों के हस्ताक्षर नहीं हैं और आधार (ड) इस आधार पर नामजुरी के लिए उपबंध करता है कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबंध में से किसी का अनुपालन नहीं हो पाया है। धारा 6 अभ्यर्थित वापस लेने के बारे में है। धारा 8 सविरोध और अविवरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया अधिकथित करती है। धारा 9 निर्वाचनों में मतदान की रीति के लिए उपबंध करती है और धारा 10 मतों की गणना के बारे में है। धारा 11 मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम की घोषणा के लिए उपबंध करती है।

3. अधिनियम के भाग III में (धारा 13 से 20) निर्वाचन संबंधी विवादों के बारे में उपबंध अंतर्विष्ट है। धारा 14 की उप-धारा (1) में विहित है कि किसी भी निर्वाचक को निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करके ही चुनौती दी जायेगी और उप-धारा (2) के अधीन इस न्यायालय को उस प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिसे निर्वाचन अर्जी पर विचारण करने की अधिकारिता होगी। धारा 14 क की उप-धारा (1) में अधिकथित है कि निर्वाचन अर्जी ऐसे निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है या राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दिशा में 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा अर्जीदारों के रूप में संयुक्त रूप से फाइल की जा सकती है। "अभ्यर्थी" शब्द की परिभाषा धारा 13 के खंड (क) में ऐसे व्यक्ति के अर्थ में की गई है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नाम निर्देशित हुआ है या सम्यक्तः नाम निर्देशित होने का दावा करता है। धारा 18 में वे आधार विहित किए गए हैं जिन पर निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है।

4. तारीख 5 जून, 1997 को भारत के राष्ट्रपति ने अधिनियम का और आगे संशोधन करने के लिए राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्या 13), जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यादेश कहा गया है, प्रख्यापित किया। उस अध्यादेश द्वारा धारा 5ख की उप-धारा (1) के खंड (क) का संशोधन किया गया था और "10 निर्वाचकों" शब्दों के स्थान पर "50 निर्वाचकों" शब्द रखे गए थे और इसके परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया था कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिए। अध्यादेश द्वारा धारा 5(ग) को भी संशोधित किया गया था और "दो हजार पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्द रखे गए थे और परिणामस्वरूप प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त की जाने वाली राशि दो हजार पांच सौ रुपये से बढ़ाकर पंद्रह हजार रुपये कर दी गई थी। उस अध्यादेश का स्थान राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन संशोधन अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्या 35) जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम कहा गया है, ले लिया। जिसे संसद ने 29 अगस्त, 1997 को अधिनियमित किया था। श्री चरण लाल साहू अर्जीदार संख्या 1 ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 293/97 फाइल की जिसमें उसने अध्यादेश की विधिमाम्यता को चुनौती दी। उक्त रिट याचिका को न्यायालय ने 9 जून, 1997 को पारित निम्नलिखित आदेश द्वारा खारिज कर दिया :—

"रिट याचिका खारिज की जाती है।"

5. एक अन्य रिट याचिका संख्या 322/97 पी. एच. परमार नामक व्यक्ति ने फाइल की थी। उक्त रिट याचिका भी इस न्यायालय में 11 जुलाई, 1997 को पारित निम्नलिखित आदेश द्वारा खारिज कर दी थी :—

"अनुच्छेद 32 के अधीन यह रिट याचिका भ्रामक है। जहां तक अध्यादेश को दी गई चुनौती का संबंध है इसका अंतिम रूप से विनिश्चय सी. एल. साहू बनाम भारत संघ और अन्य नामक एक पूर्व रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 237/97) की खारिजी से हो जाता है। हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि यह लोकहित मुकदमों की अधिकारिता का दुरुपयोग है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।"

6. संशोधन अधिनियम बनने के बाद अर्जीदार संख्या 1 ने संशोधन अधिनियम की विधिमाम्यता को चुनौती देने के लिए पुनः एक रिट याचिका संख्या डी 1334/97 फाइल की। उक्त रिट याचिका भी न्यायालय द्वारा 12 नवम्बर, 1997 को पारित निम्नलिखित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी :—

“यह रिट याचिका पूर्णतः भ्रामक है। हमारी समझ में नहीं आता कि अर्जीदार उसी बात पर क्यों जमा हुआ है जबकि हमने उसे यह बताया तो था और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि ऐसी चुनौती को रिट याचिका संख्या 293/97 और रिट याचिका संख्या 322/97 में क्रमशः तारीख 19-6-97 और 11-7-97 के आदेशों द्वारा पहले ही नामंजूर किया जा चुका है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। अतः यह रिट याचिका खारिज की जाती है।”

7. निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के बाद रिटनिंग ऑफिसर ने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन तारीख 9 जून 1997 को अधिसूचना प्रकाशित की। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में अर्जीदारों सहित अनेक व्यक्तियों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के नाम निर्देशन पत्र रिटनिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार कर लिए गए और अर्जीदारों सहित शेष के नाम निर्देशन नामंजूर कर दिए गए। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के बीच निर्वाचन लड़ा जाना था इसलिए मतदान कराया गया और मतगणना के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 को 17 जुलाई, 1997 को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तारीख 14 अगस्त, 1997 को अर्जीदारों ने यह निर्वाचन अर्जी फाइल की जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

8. अर्जीदारों ने प्राख्यान किये कि वे सम्यक्तः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी थे और निर्वाचन अर्जी फाइल करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके नाम निर्देशन अनुचित ढंग से नामंजूर किए गए थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के नाम निर्देशन अनुचित ढंग से स्वीकार किए गए थे। अर्जीदारों ने अधिनियम की धारा 5ख और 5ग जिस रूप में यह अध्यादेश द्वारा किए गए संशोधनों से पूर्व विद्यमान थी, में अंतर्विष्ट उपबंधों की विधि मान्यता को चुनौती दी है और अध्यादेश द्वारा धारा 5ख और 5ग में किए गए संशोधनों की विधिमान्यता को भी चुनौती दी है। निर्वाचन अर्जी में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि अर्जीदार संख्या 1 के नाम निर्देशन के लिए नाम निर्देशन पत्र पर 50 निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर थे, जैसा कि अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 5ख (1)(क) द्वारा अपेक्षित था। दूसरी ओर अर्जीदार संख्या 1 द्वारा रिटनिंग ऑफिसर को भेजे गए तारीख 9 जून, 1997 के पत्र में जिसे निर्वाचन अर्जी के उपबंध-III के रूप में फाइल किया गया है, अर्जीदार संख्या 1 ने कहा है कि उसका नाम निर्देशन पत्र 7 निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापित किया गया था और यह कि 50 प्रस्थापकों और 50 समर्थक अपेक्षित नहीं थे। जहां तक अर्जीदार संख्या 2 का संबंध है, निर्वाचन अर्जी में यह प्राख्यान किया गया है कि उसके नाम निर्देशन पत्र पर 64 प्रस्थापकों और 61 समर्थकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

9. निर्वाचन अर्जी के लम्बित रहते हुए अध्यादेश का स्थान संशोधन अधिनियम ने ले ली। अर्जीदारों ने निर्वाचन अर्जी के पृष्ठ 5 और 40 पर अध्यादेश के स्थान पर संशोधन अधिनियम रखने के लिए निर्वाचन अर्जी के संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया। आवेदन मंजूर किया जाता है और अर्जीदारों को निर्वाचन अर्जी में उक्त संशोधन के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

10. निर्वाचन अर्जी पर जारी की गई सूचना के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्वाचन अर्जी का उत्तर शपथ-पत्र फाइल किया गया। उक्त उत्तर शपथ-पत्र में अर्जीदारों द्वारा निर्वाचन अर्जी फाइल करने के बारे में इस आधार पर प्रारम्भिक आक्षेप किया गया है कि अर्जीदार निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं थे और वे अधिनियम की धारा 14क के अधीन निर्वाचन अर्जी दाखिल करने के हकदार नहीं हैं। रिटनिंग ऑफिसर को सम्बोधित अर्जीदार संख्या 1 के तारीख 24 जून, 1997 के पत्र का हवाला दिया गया है (निर्वाचन अर्जी का उपबंध संख्या 3) जिसमें अर्जीदार संख्या 1 ने यह दावा किया कि उसके सात प्रस्थापक थे और उसने किसी भी समर्थक का दावा नहीं किया और यह अनुपालन किया है कि उक्त पत्र से पता चलता है कि अर्जीदार संख्या 1 के पास 50 प्रस्थापक और 50 समर्थक नहीं थे। जहां तक अर्जीदार संख्या 2 के नाम निर्देशन पत्र का संबंध है उत्तर शपथ पत्र में यह कहा गया है कि नाम निर्देशन पत्र में 64 प्रस्थापकों के नामों का उल्लेख किया गया था किंतु उनमें से 29 ने उस पर बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं किए और प्रस्थापकों की संख्या केवल 35 थी। इसी प्रकार 61 समर्थकों के नाम थे किंतु उनमें 28 ने हस्ताक्षर नहीं किए और इसलिए केवल 33 समर्थक थे। यह भी कहा गया है कि अर्जीदार संख्या 2 का नाम निर्देशन शुरु में ही अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनके साथ अधिनियम की धारा 5ख(2) द्वारा अपेक्षित निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति नहीं थी। उक्त उत्तर शपथ-पत्र में निर्वाचन अर्जी में अंतर्विष्ट प्रकथनों का उत्तर गुणों के आधार पर किया गया है और इस बात से इंकार किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम निर्देशन पत्र गलत ढंग से स्वीकार किया गया था और यह प्रकथन किया गया है कि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि की प्रामाणिक प्रति दाखिल की गई थी जैसा कि अधिनियम की धारा 5ख(2) द्वारा अपेक्षित है। जहां तक अध्यादेश की विधिमान्यता को दी गई चुनौती का संबंध है, अर्जीदार संख्या 1 द्वारा फाइल की गई रिट याचिका और श्री पी. एच. परमार द्वारा फाइल की गई रिट याचिका संख्या 322/97 को खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अविलम्ब लिया गया है।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के उत्तर शपथ-पत्र के उत्तर में अर्जीदार संख्या 1 का प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया गया है। उक्त प्रत्युत्तर शपथ पत्र में, उत्तर शपथ-पत्र में किए गए इन प्रकथनों का, खंडन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम निर्देशन पत्र पर सात प्रस्थापकों द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे और अर्जीदार संख्या 2 के नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्थापकों के रूप में 35 निर्वाचकों द्वारा तथा समर्थकों के बारे में 33 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह कि अर्जीदार संख्या 2 के नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई थी। अतः हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि दोनों अर्जीदारों के नाम निर्देशन पत्र के अधिनियम की 5ख(1) की अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति नहीं करती थी क्योंकि उनमें से किसी भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्थापकों के रूप में अपेक्षित 50 निर्वाचकों के और समर्थकों के रूप में अपेक्षित 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर नहीं थे और यह कि जहां तक अर्जीदार संख्या 1 का संबंध है उसके नाम निर्देशन पत्र पर 10 प्रस्थापकों के भी हस्ताक्षर नहीं थे बल्कि सात प्रस्थापकों के हस्ताक्षर थे और यह कि अर्जीदार संख्या 2 का नाम निर्देशन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना दाखिल किया गया था।

12. अधिनियम के भाग 3 के अधीन फाइल की गई निर्वाचन अर्जी के संबंध में लागू नियम उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश 39 में

अंतर्विष्ट है। आदेश 39 के नियम 34 के उपबंध है कि उक्त आदेश या न्यायालय के किसी विशेष आदेश या निर्देश के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन अर्जी फाइल करने पर जहां तक हो सके वह प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो न्यायालय के समक्ष उसकी आरम्भिक अधिकारिता के उपयोग में आरंभ की गई कार्रवाईयों में अपनाई जाती है। जहां तक न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता के उपयोग में कार्रवाईयों का संबंध है आदेश 23 के नियम 6 में उपबंधित यह है कि वाद पत्र नामजूर कर दिया जाएगा—(क) उसमें वाद हेतुक प्रकट न किया गया हो अथवा (ख) जहां वाद पत्र में किए गए कथनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

13. उत्तर शपथ में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया गया आरम्भिक आक्षेप यह है कि अर्जीदार अधिनियम की धारा 14क की दृष्टि से निर्वाचन अर्जी फाइल करने के लिए हकदार नहीं है क्योंकि वे निर्वाचन में अभ्यर्थी नहीं थे। यदि उक्त प्रारम्भिक आक्षेप स्वीकार कर लिया जाए तो निर्वाचन अर्जी विधि द्वारा अर्थात् अधिनियम की धारा 14क द्वारा वर्जित होने के कारण नामजूर हो सकती है। अतः हमने उक्त प्रारम्भिक आक्षेप के बारे में अर्जीदारों एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान का उत्सेल को और भारत के विद्वान महान्यायवादी को सुना।

14. निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करने से संबंधित अधिनियम की धारा 14क में यह उपबंध किया है :—

14क (1) निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली अर्जी धारा 18 की उपधारा (1) में और धारा 19 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, या —

- (i) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में,
- (ii) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में,

उच्चतम न्यायालय में पेश की जा सकेगी।

(2) ऐसी कोई अर्जी उस घोषणा के, जिसमें धारा 12 के अधीन निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम हो, प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय पेश की जा सकेगी किंतु ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् पेश नहीं की जा सकेगी।

15. "अभ्यर्थी" शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 13क में निम्न प्रकार दी गई है :—

- (क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट हुआ है या सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है।

16. "निर्वाचक" शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(ब) में इस प्रकार दी गई है :—

- (घ) निर्वाचक से राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य अभिप्रेत है और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य अभिप्रेत है।

17. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल श्री सौराव जी ने प्रारम्भिक आक्षेप के समर्थन में बहस करते हुए यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति निर्वाचन को प्रश्नगत करते हुए निर्वाचन अर्जी या तो ऐसे निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी द्वारा या 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा अर्जीदारों के रूप में संयुक्त रूप से फाइल की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में निर्वाचन अर्जी 20 या अधिक निर्वाचकों द्वारा अर्जीदारों के रूप में संयुक्त रूप से फाइल नहीं की गई है। अपितु केवल 2 अर्जीदारों द्वारा ही फाइल की गई है। इसे तभी ग्रहण किया जा सकता है जब किसी भी अर्जीदार को अभ्यर्थी माना जाए। अधिनियम की धारा 13क में अंतर्विष्ट अभ्यर्थी की परिभाषा का हवाला देते हुए श्री श्री सौराव जी ने निवेदन किया है कि न तो कोई अर्जीदार सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी था और न ही निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट होने का दावा कर सकता था क्योंकि दोनों के द्वारा प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्रों पर 50 प्रस्थापकों और 50 समर्थकों के हस्ताक्षर नहीं थे जैसाकि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 5ए(1)(क) के अनुसार अपेक्षित था। अतः निवेदन किया गया है कि अर्जीदारों को इस निर्वाचन अर्जी को फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है और चलने योग्य न होने के कारण इसे खारिज कर दिया जाएगा। यह भी दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 14क के अधीन फाइल की गई निर्वाचन अर्जी में अधिनियम की धारा 5ख और 5ग की विधिमाम्यता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और निर्वाचन अर्जी केवल अधिनियम की धारा 18 में वर्णित किन्हीं आधारों पर ही घोषित की जा सकती है। यह भी निवेदन किया गया कि किसी भी दशा में धारा 5ख और 5ग की विधिमाम्यता, जैसा कि उक्त उपबंध 5 जून, 1997 के पूर्व थे, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि नामांकन चरन लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी के मामले में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा यथा विनिश्चित 10 निर्वाचकों को प्रस्थापक के रूप में 10 निर्वाचकों को समर्थ के रूप हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस न्यायालय द्वारा तीन रिट याचिकाओं को खारिज करते समय, जिनका पहले निर्देश किया गया है और जिनमें से 2 रिट अर्जियां स्वयं अर्जीदार सं. 1 द्वारा फाइल की गई थी, अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 5ख और 5ग में पुरःस्थापित संशोधनों की विधिमाम्यता की चुनौती को अस्वीकार कर दिया है।

18. विद्वान् महा न्यायवादी ने भी यही आधार लिया है और निवेदन किया है कि चूंकि किसी भी अर्जीदार को अधिनियम की धारा 13(क) के अधीन अभ्यर्थी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता इसलिए वे अधिनियम की धारा 14(क) के अधीन निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करने के हकदार नहीं हैं इसलिए इसे आरंभ में ही खारिज किया जाना चाहिए।

19. अर्जीदार सं. 1 चरन लाल साहू ने स्वयं अर्जीदार के रूप में और अर्जीदार सं. 2 की ओर से काउन्सेल के रूप में दलील दी। उन्होंने निवेदन

किया कि दोनों अर्जीदार अधिनियम की धारा 13(क) के अधीन अभ्यर्थी हैं क्योंकि वे सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हैं। यह तर्क दिया गया कि यह अपेक्षा कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र को धारा 5ख (1)(क) में वर्णित और अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त उपबंध में पुरस्थापित संशोधन के पूर्व जैसा कि यह था, में वर्णित 10 निर्वाचकों को प्रस्थापकों के रूप में, 10 निर्वाचकों को समर्थकों के रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त उपबंध में पुरस्थापित यह अपेक्षा कि नामांकन पत्र को 50 निर्वाचकों को प्रस्थापकों के रूप में और 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए, असंवैधानिक और शून्य है। अर्जीदारों का निवेदन है कि वे निर्वाचन अर्जी में अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा पुरस्थापित संशोधनों और अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा उसमें किए गए संशोधन जो भी जैसा कि पहले था, धारा 5ख में वर्णित उपबंधों की विधिमान्यता को चुनौती देने के हकदार हैं और ऐसी चुनौती वर्जित नहीं है। यह भी दलील दी गई कि धारा 5ख की विधिमान्यता की चुनौती को अस्वीकार करने वाले पूर्व विनिश्चयों में संविधान के अनुच्छेद 55(3) में वर्णित मत-पत्र की गोपनीयता से संबंधित उपबंध पर विचार नहीं किया गया और यह कि संविधान के उक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए यह पूर्व अपेक्षा कि नामांकन पत्र 10 प्रस्थापकों और 10 समर्थकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए इसलिए 50 प्रस्थापकों और 50 समर्थकों द्वारा हस्ताक्षरित मांग की प्रस्तुत अपेक्षा असंवैधानिक है। यह तर्क दिया गया है कि यदि धारा 5ख के उक्त उपबंध को असंवैधानिक ठहराया जाए तो अर्जीदार सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी माने जाएंगे और वे यह निर्वाचन अर्जी फाइल करने के हकदार हैं।

20. अधिनियम की धारा 14क को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन अर्जी को राष्ट्रपतीय निर्वाचन को प्रश्नगत करते हुए कोई निर्वाचन अर्जी या तो ऐसे निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा या 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ अर्जीदार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह अर्जी 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा नहीं फाइल की गई है। अर्जीदार इस आधार पर अर्जी फाइल करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं कि वे निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। अर्जीदार के उक्त दावों को अधिनियम की धारा 13(क) में अन्तर्विष्ट "अभ्यर्थी" की परिभाषा के आधार पर परीक्षा की जानी चाहिए जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो निर्वाचन में सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है या अभ्यर्थी होने का दावा करता है, को 'अभ्यर्थी' माना जाता है। विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अर्जीदार, जिनके नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, को ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जिन्हें नाम निर्दिष्ट किया गया है या प्रश्नगत निर्वाचन में 'अभ्यर्थी' के सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट होने का दावा कर सकता है।

21. चरन लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी<sup>1</sup> के मामले में इस न्यायालय ने अर्जीदार (यहां अर्जीदार सं. 1) के सुने जाने के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया जिसने निर्वाचन अर्जी फाइल की थी। उस मामले में भी निर्वाचन अर्जी, ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल की गई थी जिसका नाम निर्देशन उस समय लागू धारा 5ख(1)(क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अपेक्षित संख्या में प्रस्थापकों और समर्थकों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अर्जीदार को निर्वाचन की चुनौती देने और अर्जी दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहने के पश्चात् कि अर्जीदार ने अर्जी में यह स्वीकार किया कि वह अधिनियम की धारा 5ख द्वारा यथा उपबंधित नाम निर्दिष्ट नहीं था और अधिनियम की धारा 5ग द्वारा यथा अपेक्षित धन भी जमा नहीं किया था, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :—

"इस प्रकार, अर्जी या वाद पत्र में यह स्वीकार करने पर, अर्जीदार, या तो सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी नहीं था या वह इस प्रकार नाम निर्दिष्ट होने का दावा नहीं कर सकता।"

22. पुनः चरन लाल साहू और अन्य बनाम ज्ञानी जैल सिंह और अन्य<sup>2</sup> के मामले में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दो अर्जीदारों के जिन्होंने निर्वाचन अर्जी फाइल की थी, फाइल किए गए नामांकन पत्र प्रस्थापकों के रूप में 10 निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में 10 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। अर्जीदारों की ओर से दलील दी गई यदि यह अभिनिर्धारित भी किया जाए कि वे सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी नहीं हैं फिर भी उस आधार पर निर्वाचन अर्जी खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि वह "सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट होने का दावा कर रहे हैं।" उक्त दलील को नामंजूर करते हुए इस न्यायालय ने कहा :—

"यह सच है कि अभ्यर्थिता के दावे के विषय में, ऐसा व्यक्ति जो कि वह दावा करता है कि उसे सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट कर दिया गया है, उस व्यक्ति के समान है, जिसे वास्तव में सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया था किन्तु सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट किए जाने का दावा ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका नामनिर्देशन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) की आज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। अर्थात् यह कि ऐसा व्यक्ति जिसके नामनिर्देशन पत्र पर, स्वीकृततः प्रस्थापकों और समर्थकों के रूप में अपेक्षित संख्या के निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, यह दावा नहीं कर सकता कि उसे सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया था। ऐसा दावा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो यह दर्शा कर सके कि उसका नामनिर्देशन-पत्र धारा 5ख(1)(क) के उपबंधों के अनुसार था, किन्तु फिर भी जिसे रिटर्निंग आफिसर ने अस्वीकृत कर दिया था, अर्थात् यह कि उसे गलत ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया था। उदाहरणार्थ, यदि रिटर्निंग आफिसर इस आधार पर नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत करता है कि दस हस्ताक्षरकर्ताओं में से, जिन्होंने कि नामनिर्देशन के लिए प्रस्थापना की थी, एक निर्वाचक नहीं है, तो अर्जीदार यह दावा कर सकता है कि उसे उस दिशा में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि उसने यह साबित कर दिया है कि उक्त प्रस्थापक वास्तव में निर्वाचक था।

इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए यह दावा करने का अवसर, कि उसे सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया था, केवल तभी आ सकती है, यदि उसका नामनिर्देशन-पत्र उन कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है जो कि नामनिर्देशन-पत्र के फाइल करने की बात को शासित करती है न कि अन्यथा। इस दावे में कि उसे सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया था, आवश्यक रूप से यह विवक्षित है और उसमें यह दावा अन्तर्ग्रस्त है कि उसका नामनिर्देशन-पत्र कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार था। अतः, निर्वाचन लड़ने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके नामनिर्देशन-पत्र पर प्रस्थापकों

1. 1978 (3) एस. सी. आर.

2. 1974 (2) एस. सी. आर. 6: [1984]<sup>2</sup>-उप. वि.प.-833

के रूप में कम से कम दस निर्वाचकों ने और समर्थकों के रूप में कम से कम दस निर्वाचकों ने हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) द्वारा अपेक्षित है, यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले की बनिस्पात जिसने अपने ही नामनिर्देशन के संबंध में अपनी सहमति नहीं दी है, किसी भी प्रकार से अधिक सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है, दावा कर सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्ति का यह दावा कि उसे सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया था, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन से अवश्य ही उद्भूत होना चाहिए। वह अधिनियम के अतिक्रमण से किसी भी प्रकार से उद्भूत नहीं हो सकता। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जिसने अपना नामनिर्देशन-पत्र बिल्कुल ही फाइल नहीं किया था किन्तु जिसने मौखिक रूप से रिटर्निंग आफिसर को यह इत्तिला दे दी थी कि वह निर्वाचन लड़ना चाहता है, यह दलील दे सकता है कि उसे अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है।''

23. मिथिलेश कुमार सिन्हा आदि बनाम राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर और अन्य<sup>1</sup> के मामले में अर्जीदार सं. 2 द्वारा फाइल की गई निर्वाचन अर्जी के संबंध में वही प्रश्न उठाया जिसका नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इस प्रकार अपेक्षित संख्या में प्रस्थापकों और समर्थकों के हस्ताक्षर नहीं हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रस्थापकों और समर्थकों ने जिन्होंने अर्जीदार सं. 2 के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, में पहले ही दूसरे अभ्यर्थी के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे। ऐसे प्रस्थापकों और समर्थकों के पश्चात्पूर्ति हस्ताक्षर अर्जीदार सं. 2 के नामांकन पत्र पर निर्वाचन अर्जी को इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि अर्जीदार सं. 2 का नामांकन पत्र धारा 5ख(1)(क) की आज्ञापक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता इसलिए उन्हें अर्जी फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है। वह अभिनिर्धारित किया गया :—

“किसी निर्वाचन को प्रश्नगत करने के लिए कोई निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करने के लिए हकदार बनाने हेतु अर्जीदार को ऐसे निर्वाचन में धारा 13-क के अर्थान्तर्गत एक ‘अभ्यर्थी’ होना चाहिए, जिसके लिए उसे ‘अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नाम-निर्देशित’ होना चाहिए और ऐसा दावा वह तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि धारा 5-ख(1)(क) और धारा 5-ग की आज्ञापक अपेक्षाओं का उसके द्वारा पालन न कर दिया गया हो। जहां पर अविवादस्पद तथ्यों के आधार पर किसी विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए इन आज्ञापक अपेक्षाओं में किसी अपेक्षा का पालन नहीं किया गया था, वहां पर उक्त अर्जीदार धारा 13-क के अर्थान्तर्गत एक अभ्यर्थी नहीं था और इसलिए धारा 14-क के अनुसार वह अर्जी प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं था।

इस न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा यह भी सुस्थिर है कि उक्त अधिनियम की धारा 14-क के अनुसार ऐसी कोई निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करने के लिए हकदार बनाने हेतु धारा 13(क) के अर्थान्तर्गत एक अभ्यर्थी के रूप में अपेक्षित सुने जाने का अधिकार रखने के लिए अर्जीदार को धारा 5-ख(1)(क) और धारा 5-ग के अनुसार एक अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है, तब तक अर्जीदार यह भी दावा नहीं कर सकता कि उसे उक्त निर्वाचन में एक अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया था, जैसा कि धारा 13(क) द्वारा अपेक्षित है। (पृष्ठ 685-686)

24. उपरोक्त निर्दिष्ट विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि कोई भी याची अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित उक्त पद के अनुसार ‘अभ्यर्थी’ नहीं है क्योंकि न तो उनमें से कोई सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किए गए न ही वे अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट होने का दावा कर सकते हैं चूंकि उनमें से दोनों के द्वारा फाइल किए गए नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) की आज्ञापक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते और अर्जीदार सं. 2 का नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(2) की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना फाइल किया गया। उस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि किसी भी अर्जीदार को अर्जी फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है।

25. धारा 5ख और 5ग, जैसे कि वे 5 जून, 1997 के पूर्व थे, उपबंधों की विधिमान्यता के संबंध में अर्जीदारों की और से दिए गए तर्क के संबंध में कहा जा सकता है कि उपबंधों की विधिमान्यता को चरन लाल साहू बनाम श्री फखरुद्दीन अली अहमद और अन्य<sup>2</sup>, चरन लाल साहू बनाम नीलम संजीव रेड्डी<sup>3</sup>, चरन लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह<sup>4</sup> के मामलों में इस न्यायालय द्वारा कायम रखा गया है। अर्जीदार सं. 1 इन सभी विनिश्चयों में एक पक्षकार था। अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा पुनः स्थापित संशोधनों की विधिमान्यता की चुनौती को इस न्यायालय ने, उपरोक्त निर्दिष्ट तीन अर्जियों में, जिनमें से दो अर्जीदार सं. 1 द्वारा फाइल की गई थी, अस्वीकार कर दिया गया है। अर्जीदारों ने यह तर्क दिया कि इस अर्जी में धारा 5ख की विधिमान्यता की चुनौती इस आधार पर आधारित है कि यह संविधान के अनुच्छेद 55(3) के मतपत्र की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और यह कि इस आधार पर पूर्व विनिश्चयों में विचार नहीं किया गया था। हम इस दलील में कोई सार नहीं पाते। प्रस्थापकों और समर्थकों के रूप में निर्वाचकों के किसी विशिष्ट संख्या द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में धारा 5ख(1)(क) की अपेक्षा किसी तरह निर्वाचन के मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करता चूंकि ऐसा निर्वाचक, जिसने किसी व्यक्ति के नामांकन पत्र पर प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया है, अपना मत किसी अभ्यर्थी के पक्ष में देने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे व्यक्ति के लिए मत देने के लिए बाध्य नहीं है जिसके नामांकन पत्र उसने प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। अभ्यर्थी की यह पहचान कि किसके पक्ष में उसने अपना मत दिया, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।

26. अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) की अपेक्षा को पूरा करने के संबंध में अर्जीदार सं. 1 ने निवेदन किया कि उसके नामांकन पत्र पर प्रस्थापकों के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सात सदस्यों द्वारा और समर्थकों के रूप में उक्त सभा के 6 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह उल्लेख किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 55(2) के उपबंधों के अनुसार जारी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य के कथन के अनुसार उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य 208 है जबकि अरुणाचल प्रदेश के विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य 8 है। निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सात सदस्यों के मतों का समेकित मूल्य जिन्होंने प्रस्थापकों के रूप में अर्जीदार सं. 1 के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए

1. 1972 (1) एस. सी. आर. सप्ती. 651 : [1982<sup>2</sup>-उप. नि.प.-486

2. एस. सी. आर. 1975 एम. सी. 1288

3. 1978 (3) एस. सी. आर. 1

4. 1984 (2) एस. सी. आर. 6

और 6 सदस्य जिन्होंने समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए, का मूल्य अरुणाचल प्रदेश के विधान सभा के 50 सदस्यों के मतों के मूल्य से काफी अधिक है इसलिए अर्जीदार सं. 1 के नामांकन पत्र को प्रस्थापकों और समर्थकों के 50 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया माना जाना चाहिए। धारा 5ख(1)(क) के अधीन जो अपेक्षित है वह यह है कि नामांकन पत्र प्रस्थापकों के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के संबंध में पद "निर्वाचक" को अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य है। अनुच्छेद 54 के अधीन राज्य के विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचक सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण का सदस्य है। दूसरे शब्दों में, राज्य विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अधिनियम की धारा 2(घ) के अधीन निर्वाचक है। अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) के प्रयोजन के लिए नामांकन पत्र पर राज्य विधान सभाओं या संसद के सदस्यों की अपेक्षित संख्या में प्रस्थापकों और समर्थकों के रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए और एक सदस्य के मतों के मूल्य के संबंध में अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) में अधिकथित उक्त अपेक्षा का कोई महत्व नहीं है।

27. उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि चूंकि अर्जीदारों का नामांकन पत्र अधिनियम की धारा 5ख(1)(क) की आज्ञापक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता और अर्जीदार सं. 2 भी अधिनियम की धारा 5ख(2) की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा, इसलिए अर्जीदार निर्वाचन में सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी नहीं माने गए और वे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट होने का दावा नहीं कर सकते और वे अधिनियम की धारा 13(क) के अधीन "अभ्यर्थी" नहीं माने जा सकते। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उठाया गया आरंभिक आक्षेप, यह है कि अर्जीदार निर्वाचन अर्जी दायर नहीं कर सकते, स्वीकार किया जा सकता और केवल इस आधार पर ही निर्वाचन अर्जी खारिज हो जानी चाहिए।

28. निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व हम उस पहलू का उल्लेख करना चाहते हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस निर्वाचन अर्जी को फाइल करने के पूर्व अर्जीदार सं. 1 ने वर्ष 1974, 1977 और 1982 में हुए राष्ट्रपति निर्वाचनों में निर्वाचित अभ्यर्थियों के निर्वाचन की चुनौती देते हुए 3 निर्वाचन अर्जी पहले भी फाइल की थीं। ये सभी निर्वाचन अर्जियां इस आधार पर खारिज की गईं कि अर्जीदार को निर्वाचन अर्जी कायम करने का कोई अधिकार नहीं है। (चरन लाल साहू बनाम फकरुद्दीन अली अहमद और अन्य, चरन लाल साहू बनाम श्री नीलम संजीव रेड्डी, चरन लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह, देखिए)। इसी प्रकार अर्जीदार सं. 2 ने वर्ष 1987 और वर्ष 1992 में हुए राष्ट्रपतीय निर्वाचनों में निर्वाचित अभ्यर्थियों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दो निर्वाचन अर्जियां फाइल की थीं। ये दोनों निर्वाचन अर्जियां इस आधार पर खारिज की गईं कि अर्जीदार को निर्वाचन अर्जी कायम करने का कोई अधिकार नहीं था। (मिथिलेश कुमार बनाम श्री आर. वेंकटरमन, और अन्य, मिथिलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, देखिए)। चरन लाल साहू बनाम ज्ञानी जैल सिंह के मामले में अर्जीदार सं. 1 द्वारा फाइल की गई निर्वाचन अर्जी को निर्दिष्ट करते समय न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :—

"यह खेद का विषय है कि भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन अर्जियां इतनी अभद्र ढंग से फाइल की जाएं जैसे कि ये दोनों निर्वाचन अर्जियां फाइल की गई हैं। इन अर्जियों पर दुबारा विचार तो किया ही नहीं गया है, इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि वे बिना तैयारी के पेश की गई हैं और इन निर्वाचन अर्जियों के प्रारूपण के मामले में कोई भी तैयारी नहीं की गई है या उनमें जो दलीलें पेश की गई हैं उनके संबंध में भी कोई तैयारी नहीं की गई है। ऐसी अर्जियों के फाइल करने की बात को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, यदि हम इन दोनों अर्जीदारों के विरुद्ध भारी खर्च के संबंध में आदेश पारित करते, तो वह न्यायोचित होता। किन्तु उसके परिणामस्वरूप अनावश्यक रूप से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता संभाव्य है कि यह न्यायालय, जो कि अधिनियम द्वारा निर्वाचन अर्जियों को विनिश्चित करने के लिए अनन्य रूप से न्यायालय के रूप में गठित किया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपतीय या उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की चुनौती दी जाती है, ऐसी अर्जियां ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक है। लोकतन्त्र के कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ही सार्वजनिक पदों के लिए जो निर्वाचन किये जाते हैं, स्वतंत्र अधिकरण द्वारा उनकी संवीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। अपने ही तथ्यों के आधार पर इन दोनों अर्जियों में भारी खर्चा संबंधी आदेश कितना ही न्यायोचित क्यों न हो, उसके परिणामस्वरूप भविष्य में साधारण दावे को प्रारंभ में ही समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिए। अतः हम खर्च के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं और इसकी बजाय हम उस हल्के-फुल्के तथा अगंभीर रीति के प्रति, जिसमें इन दोनों अर्जियों का प्रारूपण तैयार किया गया है और वे फाइल की गई हैं, अपना अनुमोदन व्यक्त करते हैं। (17)

29. मिथिलेश कुमार बनाम श्री आर. वेंकटरमन और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया :—

"हम निर्वाचन-याचिका फाइल करने के लिए पात्र शुद्ध अन्तर्करण वाले प्रत्येक नागरिक से यह आशा करते हैं कि वह अधिनियम द्वारा विहित आधारों पर निर्वाचन को प्रश्नगत करेगा, तथापि हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी याचिका इस न्यायालय का, अन्तर्वस्तु और केवल सस्ता प्रचार पाने के लिए मामले को लागू होने वाली विधि के उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना, याचिका फाइल करने के फोरम (न्यायालय) के रूप में इस न्यायालय का दुरुपयोग करे। हमें खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कुछ दिनों से प्रतिदिन समाचारपत्र में अपना नाम देखने की बुरी लत पड़ गई है और इस लत के शिकार लोगों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। (537)

1. ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1288.

2. 1978 (3) एस. सी. आर. 1.

3. 1984 (2) एस. सी. आर. 6.

4. (1988) 1 एस. सी. आर. 525.

5. 1992 (1) एस. सी. आर. सम्ली 651.

30. मिथिलेश कुमार सिन्हा बनाम राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के मामले में न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया:—

“..... अनुभव से यह दर्शित होता है कि ऐसी याचिकाओं से संलग्न पवित्रता और महत्व को उस अशिष्टतापूर्ण रीति ने ढोंग बना कर रख दिया है, जिसमें इस उपचार का अवलंब लिया जाता है। मात्र इस तथ्य से कि इन दोनों याचिकाओं की संपूर्ण परिधि पूर्णतः इस न्यायालय के अनेक पूर्वतर विनिश्चयों के अन्तर्गत आती है, जिनमें से कुछ में यही याची पक्षकार थे, यह दर्शित होता है कि विद्यमान उपबंध विधि की प्रक्रिया (कार्यवाही) के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपर्याप्त है।”

31. हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन मतों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह निर्वाचन अर्जी जो संयुक्तः दो अर्जीदारों द्वारा फाइल की गई है, में कोई सुधार नहीं लगता। यह अर्जीदारों द्वारा फाइल की गई पूर्व अर्जियों के समान उन्हीं खामियों से ग्रस्त है। यह प्रतीत होता है कि अर्जीदारों की इच्छा है कि उनके नाम किन्हीं अभिलेख पुस्तकों में आ जाएं। राष्ट्रपतीय निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन अर्जी फाइल करने का प्रलोभन होता है और इसको रोकना काफी कठिन है, यह खेद का विषय है कि अर्जीदार सं. 1 जो स्वयं अधिवक्ता है; अच्छी तरह से जानते हुए कि उनका यह आचरण विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है, इन पिछले समयों में जोर देता रहा है। यह न्यायालय जहां तक ऐसे निर्वाचन अर्जियों में खर्चा अधिरोपित करने से प्रतिवारित है जो अर्जीदारों द्वारा पहले फाइल किए गए थे। यह उचित समय है कि उन अर्जीदारों पर, जो पूर्व विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा प्राधिकृत रूप से अधिकथित विधि के बावजूद, यह अर्जी फाइल की, खर्चा अधिरोपित किया जाना चाहिए।

32. निर्वाचन अर्जी, तदनुसार, खर्चें सहित खारिज की जाती है। 10,000 रुपए का खर्चा लगाया जाता है। खर्चों की उक्त राशि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा की जाएगी। यह भी निदेश दिया जाता है कि याचियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से फाइल की गई कोई अर्जी तब तक इस न्यायालय में ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अधिरोपित खर्चों की रकम जमा नहीं की जाती।

[एस. सी. अग्रवाल]

[जी. एन. रे]

[ए. एस. आनन्द]

[एस. पी. गरुबा]

[एस. राजेन्द्र बाबू]

[फा. सं. 14/11/97—विधा. II]

नई दिल्ली,

सुषमा जैन, संयुक्त सचिव

24 नवम्बर, 1997

एवं विद्यार्थी परामर्शी

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 1998

S.O. 29(E).—In pursuance of section 20 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952) the Central Government hereby Gublishes the order made on the 24-11-1997 by the Supreme Court in Election Petition No. 1 of 1997.

### IN THE SUPREME COURT OF INDIA

#### ORIGINAL JURISDICTION

PRESIDENTIAL ELECTION PETITION NO. 1 OF 1997.

Shri Charan Lal Sahu & Anr.

.....Petitioners

Versus

Shri K. R. Narayana & Anr.

.....Respondents

### JUDGMENT

S.C. AGRAWAL, J. :

This election petition has been filed jointly by two petitioners, namely, Charan Lal Sahu and Mithelos Kumar. They have challenged the election of respondent No. 1 to the office of the President of India in the election that was held for the said



Office in pursuance of the Notification dated June 9, 1997 published by the Returning Officer Shri S. Gopalan, Secretary General, Lok Sabha. The said election was conducted under the provisions of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 [hereinafter referred to as the Act].

Part II of the Act (Sections 3 to 12) contains provisions relating to conduct of Presidential and Vice-Presidential elections. Section 3 provides for appointment of the Returning Officer and the Assistant Returning Officer/Officers by the Election Commission. Section 4(1) of the Act makes provision for issuance of a notification by the Election Commission prescribing the last date for making nominations, the date for the scrutiny of nominations, the last date for the withdrawal of candidatures, the date on which a poll shall, if necessary, be taken. Section 5 provides for giving of a public notice of election by the Returning Officer after the issuance of the notification under sub-section (1) of Section 4. Section 5A prescribes that any person may be nominated as a candidate for election to the office of President or Vice-President if he is qualified to be elected to that office under the Constitution. Section 5B provides for presentation of nomination papers and lays down the requirements for a valid nomination. Sub-Section (1) of Section 5B requires that the nomination paper completed in the prescribed form must be subscribed by the candidate as assenting to the nomination. In clause (a) of sub-section (1), as it stood prior to June 5, 1997, it was further prescribed that in the case of Presidential Elections, the nomination papers shall also be subscribed by at least ten electors as proposers and at least ten electors as seconders. Sub-section (2) of Section 5B lays down that each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector. A nomination paper to which such certified copy is not attached is required to be rejected under sub-section (4) of Section 5B. Section 5C, prior to June 5, 1997, prescribed that a candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he deposits or causes to be deposited a sum of two thousands five hundred rupees. Section 5E makes provision for scrutiny of nominations and under sub-section (3) a nomination paper can be rejected by the Returning Officer on the grounds (a) to (e) of that sub-section. Ground (C) provides for rejection of a nomination paper on the ground that it is not subscribed by the required number of proposers or seconders and ground (e) provides for rejection on the ground that there has been a failure to comply with any of the provisions of Section 5B or Section 5C. Section 6 deals with withdrawal of candidature. Section 8 lays down the procedure in contested and uncontested elections. Section 9 provides for manner of voting at elections and Section 10 deals with counting of votes. Section 11 provides for declaration of result after the counting of votes has been completed.

Part III of the Act [Sections 13 to 20] contains provisions relating to Disputes regarding elections. Sub-section (1) of Section 14 prescribes that no election shall be called in question excepting by presenting an elections petition and under sub-section (2) this Court has been specified as the authority which shall have jurisdiction to try an election petition. Sub-section (1) of Section 14A lays down that an election petition can either be presented by any candidate at such election or, in the case of Presidential elections, by twenty or more electors joined together as petitioners. The expressions "candidate" is defined in clause (a) of Section 13 to mean a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at an election. Section 18 prescribes the grounds on which the election of a returned candidate can be declared to be void.

On June 5, 1997 the President of India promulgated the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Ordinance, 1997 (No. 13 of 1997), hereinafter referred to as 'the Ordinance', to further amend the Act. By the Ordinance clause (a) of sub-section (1) Section 5B was amended and for the words "ten electors" the words "fifty electors" were substituted and as a result it became necessary that a nomination paper for Presidential election should be subscribed by at least fifty electors as proposers and at least fifty electors as seconders by the Ordinance. Section 5C was also amended and for the words "two thousands five hundred rupees" the words "fifteen thousands rupees" were substituted and as a result the amount to be deposited as security was raised from two thousand five hundred rupees to fifteen thousand rupees. The Ordinance was replaced by the Presidential and Vice-Presidential Elections Amendment Act, 1997 [Act 35 of 1997], hereinafter referred to as 'the Amendment Act', which was enacted by Parliament on August 29, 1997. Charan Lal Sahu, petitioner No. 1, filed a writ petition [No. 293/97] in this Court under Article 32 of the Constitution wherein he challenged the validity of the Ordinance. The said writ petition was dismissed by the Court by the following order passed on June 9, 1997 :—

"The writ petition is dismissed"

Another writ petition [No. 322/97] was filed by one P. H. Parmar. The said writ petition was also dismissed by the Court by the following order passed on July 11, 1997 :—

"This writ petition under Article 32 is misconceived. So far as the challenge to the Ordinance is concerned, this stands concluded by dismissal of an earlier writ petition. W. P. No. 237/97 entitled C.L. Sahu vs. UOI & Ors.]. We are constrained to observe that this is misuse of the PIL jurisdiction.

The writ petition is dismissed."

After the enactment of the Amendment Act, petitioner No. 1 again filed a writ petition [No. D13334/97] to challenge the validity of the Amendment Act. The said writ petition was also dismissed by the Court by the following order passed on October 13, 1997 :—

"This writ petition is wholly misconceived. We are unable to appreciate the petitioner's persistence with the same even after we told him so and also in view of the fact that a similar challenge has already been rejected

earlier by orders dated 19-6-1997 and 11-7-1997 in W.P. (C) No. 293/97 and W.P. (C) No. 322/97 respectively. We have no doubt that this petition is clear abuse of the process of the Court.

The writ petition is, therefore, dismissed."

After the issuance of the notification under Section 4(1) of the Act by the Election Commission the Returning Officer published a notification dated June 9, 1997 under Section 5 of the Act for election of the President of India. In response to the said notification nomination forms were filed by a number of persons including the petitioners. The nominations of respondent Nos. 1 and 2 were accepted and the nominations of the rest, including the petitioners, were rejected by the Returning Officer. Since there was a contest between respondents Nos. 1 and 2, poll was taken and after counting of votes, respondent No. 1 was declared to have been elected to the office of the President of India on July 17, 1997. On August 14, 1997 the petitioners filed this election petition wherein they have prayed that the election of respondent No. 1 be declared void.

The petitioners have asserted that they were duly nominated candidates and are competent to file the election petition. They have claimed that their nomination was improperly rejected and the nomination of respondent Nos. 1 and 2 was improperly accepted. The petitioners have challenged the validity of the provisions contained in Sections 5B and 5C of the Act as they stood prior to the amendments introduced in the said provisions by the Ordinance and have also challenged the validity of the amendments made in Sections 5B and 5C by the Ordinance. There is no averment in the election petition that the nomination form for nomination of petitioner No. 1 was subscribed by fifty electors as proposers and fifty electors as seconders as required by Section 5B(1) (a), as amended by the Ordinance. On the other hand, in the letter dated June 24, 1997 addressed by the petitioner No. 1 to the Returning Officer which has been filed as Annexure III to the Election petition, petitioner No. 1 has stated that his nomination paper was proposed by seven electors and that fifty proposers and fifty seconders were not required. As regards petitioner No. 2, it has been asserted in the Election petition that his nomination paper was signed by 64 proposers and 61 seconders.

During the pendency of the election petition the Ordinance was replaced by the Amendment Act. The petitioners have filed an application for amendment of the election petition to substitute the Ordinance by the Amendment Act at pages 35 and 40 of the election petition. The application is allowed and the petitioners are permitted to carry out the said amendment in the election petition.

In response to the notice issued on the Election petition an Affidavit-in-Opposition to the Election petition has been filed by respondent No. 1. In the said Affidavit-in-Opposition a preliminary objection has been raised with regard to the maintainability of the Election petition by the petitioners on the ground that the petitioners were not candidates at the election and they are not entitled to maintain the Election petition under Section 14A of the Act. Reference has been made to the letter of petitioner No. 1 dated June 24, 1997 addressed to the Returning Officer (Annexure III to the Election petition) wherein petitioner No. 1 had claimed that he had seven proposers and did not claim any seconders at all and it is submitted that the said letter shows that petitioner No. 1 did not have fifty proposers and fifty seconders. As regards the nomination paper of petitioner No. 2 it is stated in the Affidavit-in-Opposition that in the nomination paper names of 64 proposers had been mentioned but 29 out of them had not subscribed their signatures at all and, therefore, the number of proposers was 35 only. Similarly, there were names of 61 seconders but out of them 28 did not sign and, therefore, there were only 33 seconders. It is also stated that the nomination of petitioner No. 2 was rejected on the threshold as it was not accompanied by the certified copy of the electoral roll as required under Section 5B(2) of the Act. In the said Affidavit-in-Opposition reply has also been given to the averments contained in the Election petition on merits and it is denied that the nomination paper of respondent No. 1 was wrongfully accepted and it is asserted that the certified copy of the entry in the electoral roll was filed as required under Section 5B(2) of the Act. As regards challenge to the validity of the Ordinance, reliance has been placed on the orders of this Court dismissing W.P. (Civil) No. 293 of 1997 filed by petitioner No. 1 and W. P. No. 322 of 1997 filed by Shri P. H. Parmar.

Rejoinder affidavit of petitioner No. 1 has been filed in reply to the said Affidavit-in-Opposition of respondent No. 1. In the said rejoinder affidavit the averments in the affidavit-in-Opposition that the nomination paper of petitioner No. 1 was only subscribed by 7 proposers and the nomination paper of petitioner No. 2 was subscribed by 35 electors as proposers and 33 electors as seconders and that the nomination paper of petitioner No. 2 was not accompanied by the certified copy of the electoral roll have not been controverted. We must, therefore, proceed on the basis that the nomination papers of both the petitioners did not fulfil the requirements of Section 5B(1) (a) of the Act inasmuch as neither of these nomination papers was subscribed by the requisite number of fifty electors as proposers and fifty electors as seconders and that in so far as petitioner No. 1 is concerned, his nomination paper was not even subscribed by ten proposers but was subscribed by seven proposers only and further that the nomination paper of petitioner No. 2 was filed without complying with the requirements of Section 5B(2) of the Act.

Rules governing election petition filed under Part III of the Act are contained in Order XXXIX of the Supreme Court Rules, 1966. Rule 34 of Order XXXIX provides that subject to the provisions of the said order or any special order or direction of the Court the procedure on an election petition shall follow, as nearly as may be, the procedure in proceedings before the Court in the exercise of its original jurisdiction. As regards proceedings in the exercise of the original jurisdiction of the Court

order XXIII Rule 6 provides that the plaint shall be rejected (a) where it does not disclose a cause of action, or (b) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law.

The preliminary objection raised by respondent No. 1 in the Affidavit-in-Opposition is that the petitioners are not entitled to maintain the Election petition in view of Section 14A of the Act since they were not candidates at the election. If the said preliminary objection is accepted, the election petition will be liable to be rejected as being barred by law, i.e., Section 14A of the Act. We have, therefore, heard the petitioners as well as the learned counsel for respondent No. 1 and the learned Attorney General of India on the said preliminary objection.

Section 14A of the Act relating to the presentation of the election petition provides as follows :—

“14A. (1) An Election petition calling in question an election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of section 18 and section 19 to the Supreme Court by any candidate at such election, or—

- (i) in the case of Presidential election, by twenty or more electors joined together as petitioners;
  - (ii) in the case of Vice-Presidential election, by ten or more electors joined together as petitioners.
- (2) Any such petition may be presented at any time after the date of publication of the declaration containing the name of the returned candidate at the election under section 12 but not later than thirty days from the date of such declaration.”

The word “candidate” is defined in section 13(a) of the Act as under :

“(a) candidate means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at an election;”

The word “elector” is defined in section 2(d) of the Act in these terms :

“(d) “elector”, in relation to a Presidential election, means a member of the electoral college referred to in article 54, and in relation to a Vice-Presidential election, means a member of the electoral college referred to in article 66;”

Shri Sorabjee, the learned senior counsel appearing for respondent No. 1, arguing in support of the preliminary objection, has urged that an election petition calling in question the Presidential election can either be filed by a candidate at such election or by twenty or more electors joined together as petitioners. In the present case the election petition has not been filed by twenty or more electors joined together as petitioners but has been filed by two petitioners only. It can be entertained only if either of the petitioners can be held to be a “candidate”. Referring to the definition of “candidate” contained in Section 13(a) of the Act, Shri Sorabjee has submitted that neither of the petitioners was a duly nominated candidate nor could he claim to have been duly nominated as a candidate at an election since the nomination papers submitted by both of them were not subscribed by fifty proposers and fifty seconders as required under Section 5B(1)(a) of the Act, as amended by the Amendment Act. It is, therefore, submitted that the petitioners have no locus standi to file this election petition and it should be dismissed as not maintainable. It has also been urged that the question as to the validity of Sections 5B and 5C of the Act, cannot be raised in an election petition filed under Section 14A of the Act and that an Election petition can be maintained only on any of the grounds mentioned in Section 18 of the Act. It has also been submitted that in any event the validity of Sections 5B and 5C, as the said provisions stood prior to June 5, 1997, requiring that the nomination should be subscribed by ten electors as proposers and ten electors as seconders has been upheld in Charan Lal Sahu vs. Neelam Sanjeeva Reddy, 1978 (3) SCR 1, decided by a bench of 7 judges of this Court and that the challenge to the validity of the amendments introduced in Sections 5B and 5C by the Ordinance and the Amendment Act has been negatived by this Court while dismissing the three writ petitions to which reference has been made earlier and that two of these writ petitions were filed by petitioner No. 1 himself.

The learned Attorney General has also taken the same stand and has submitted that since neither of the petitioners can be held to be a candidate under Section 13(a) of the Act they are not entitled to maintain the Election petition under Section 14A of the Act and that the same is liable to be dismissed at the threshold.

Petitioner No. 1, Charan Lal Sahu, has argued the case of petitioner-in-person and as counsel representing petitioner No. 2. He has submitted that both the petitioners were candidates under section 13(a) of the Act since they were duly nominated candidates. It has been urged that the requirement that the nomination paper for the Presidential election should be subscribed by ten electors as proposers and ten electors as seconders contained in Section 5B(1)(a), as it stood prior to the amendment introduced in the said provision by the Ordinance and the Amendment Act and the requirement introduced in the said provision by the Ordinance and the Amendment Act that the nomination paper should be subscribed by fifty electors as proposers and fifty electors as seconders, is unconstitutional and void. The submission of the petitioners is that they are entitled to challenge the validity of the provisions contained in Section 5B, as it stood prior to the amendments introduced by the Ordinance and the Amendment Act and also the amendment made therein by the Ordinance and the Amendment Act in the election petition and that such a challenge is not barred. It has been contended that the earlier decisions negativing the challenge to the validity of Section 5B did not take into consideration the provision regarding secrecy of ballot contained in

article 55(3) of the Constitution and that in view of the said provision in the Constitution the earlier requirement that the nomination paper must be subscribed by ten proposers and ten seconders and the present requirement about subscription by fifty proposers and fifty seconders is unconstitutional. It is urged that if the said provision in Section 5B is held to be unconstitutional then the petitioners must be regarded as duly nominated candidates and they are entitled to file this Election petition.

In view of Section 14A of the Act an election petition calling in question a Presidential election can be presented either by a candidate at such election or twenty or more electors joined together as petitioners. This petition has not been filed by twenty or more electors and the petitioners are claiming the right to file the petition on the basis that they were candidates at the election. The said claim of the petitioners has to be examined on the basis of the definition of "candidate" as contained in Section 13(a) of the Act where under a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at an election is to be treated as a 'candidate'. The question for consideration is whether the petitioners, whose nomination papers did not satisfy the requirements of Section 5B(1)(a) of the Act, can be regarded as persons who had been nominated or can claim to have been duly nominated as 'candidate' at the election in question.

In Charan Lal Sahu vs. Neelam Sanjeeva Reddy, [supra], this Court has dealt with the question of locus standi of the petitioner (No. 1 herein) who had filed the Election petition. In that case also the Election petition was filed by a person whose nomination was not subscribed by the requisite number of proposers and seconders as per the provisions contained in Section 5B(1)(a) applicable at that time. This Court held that the petitioner had no locus standi to challenge the election and to maintain the petition. After stating that the petitioner had admitted in the petition that he was not nominated as provided by Section 5B of the Act and had also not deposited the sum of money as required by Section 5C of the Act, the Court has held :—

"Thus, on the very admissions in the petition or plaint, the petitioner was not a candidate either duly nominated or one who could claim to be so nominated". [pp. 5.6]

Again in Charan Lal Sahu & Ors. vs. Giani Zail Singh & Anr., 1984 (2) SCR 6, it was found that the nomination papers filed of the two petitioners who had filed the election petition were not subscribed by ten electors as proposers and ten electors as seconders. It was contended on behalf of the petitioner that even if it is held that they were not duly nominated as candidates, the election petitions could not be dismissed on that ground since they were "claiming to have been duly nominated as candidates". Rejecting the said contention this Court said :—

"It is true that in the matter of claim to candidacy, a person who claims to have been duly nominated is on par with a person who, in fact, was duly nominated. But the claim to have been duly nominated cannot be made by a person whose nomination paper does not comply with the mandatory requirement of Section 5B(1)(a) of the Act. That is to say, a person whose nomination paper, admittedly, was not subscribed by the requisite number of electors as proposers and seconders cannot claim that he was duly nominated. Such a claim can only be made by a person who can show that his nomination paper conformed to the provisions of Section 5B and yet it was rejected, that is, wrongly rejected by the Returning Officer. To illustrate, if the Returning Officer rejects a nomination paper on the ground that one of the ten subscribers who had proposed the nomination is not an elector; the petitioner can claim to have been duly nominated if he proves that the said proposer was in fact an 'elector'."

"Thus, the occasion for a person to make a claim that he was duly nominated can arise only if his nomination paper complies with the statutory requirements which govern the filing of nomination papers and not otherwise. The claim that he was 'duly' nominated necessarily implies and involves the claim that his nomination paper conformed to the requirements of the statute. Therefore, a contestant whose nomination paper is not subscribed by at least ten electors as proposers and ten electors as seconders, as required by Section 5B (1)(a) of the Act, cannot claim to have been duly nominated, any more than a contestant who had not subscribed his assent to his own nomination can. The claim of a contestant that he was duly nominated must arise out of his compliance with the provisions of the Act. It cannot arise out of the violation of the Act. Otherwise, a person who had not filed any nomination paper at all but who had only informed the Returning Officer orally that he desired to contest the election could also contend that he 'Claims to have been duly nominated as a candidate'." [pp.15-16]

In Mithilesh Kumar Sinha etc. vs. Returning Officer for Presidential Election & Ors. etc., 1992 (1) SCR Supp. 651, the same question arose with regard to the election petition filed by petitioner No. 2 whose nomination paper had been rejected on the ground that it was not subscribed by the requisite number of proposers and seconders since some of the proposers and seconders who had subscribed to the nomination paper of petitioner No. 2 had earlier subscribed to the nomination paper of another candidate and the subsequent signatures of such proposers and seconders had become inoperative on the nomination paper of petitioner No. 2. The Election petition filed by petitioner No. 2 was rejected by this Court on the ground that since nomination paper of petitioner No. 2 did not comply with the mandatory requirements of Section 5B(1)(a) he had no *locus standi* to file the petition. It has been held :—

"To be entitled to present an election petition calling in question an election, the petitioner should have been a 'candidate' at such election within the meaning of Section 13(a) for which he should have been 'duly nominated as

a candidate' and this he cannot claim unless the mandatory requirements of Section 5B (1)(a) and Section 5C were complied with by him. Where on undisputed facts there was non-compliance of any of these mandatory requirements for a valid nomination, the petitioner was not a 'candidate, within the meaning of Section 13(a) and, therefore, not competent according to Section 14A to present the petition."

"It is also settled by the decisions of this Court that in order to have the requisite locus stand as a 'candidate' within the meaning of Section 13(a) for being entitled to present such an election petition in accordance with Section 14A of the Act the petitioner must be duly nominated as a candidate in accordance with Section 5B(1)(a) and Section 5C. Unless it is so the petitioner cannot even claim to have been duly nominated as a candidate at the election as required by Section 13(a). [pp. 685-686]

In view of the decisions referred to above, it must be held that neither of the petitioners was a 'candidate' as the said expression is defined in section 2(d) of the Act since neither of them had been duly nominated nor could he claim to have been nominated as a candidate inasmuch as the nomination papers filed by both of them did not comply with the mandatory requirements of Section 5B(1)(a) of the Act and the nomination paper of petitioner No. 2 was filed without complying with the requirements of Section 5B(2) of the Act. On that view it must be held that neither of the petitioners has the *locus standi* to maintain the petition.

As regards the submission urged on behalf of the petitioners regarding the validity of the provisions of Sections 5B and 5C as they stood prior to June 5, 1997, it may be stated that the validity of the said provisions has been upheld by this Court in *Charan Lal Sahu Vs. Shri Fakruddin Ali Ahmed & Ors.*, AIR 1975 SC 1288; *Charan Lal Sahu vs. Neelam Sanjeeva Reddy* [supra] and *Charan Lal Sahu vs. Giani Zail Singh* [supra]. Petitioner No. 1 was a party to all these decisions. The challenge to the validity of the amendments introduced by the Ordinance and the Amendment Act has been negated by this Court in the three writ petitions referred to above, two out of which were filed by petitioner No. 1. The petitioners have urged that in this petition the challenge to the validity of Section 5B is based on the ground that it violates the principle of secrecy of ballot incorporated in Article 55(3) of the Constitution and that this ground has not been considered in the earlier decisions. We do not find any merit in this contention. The requirement in Section 5B(1)(a) about the nomination paper being subscribed by a particular number of electors as proposers and seconders does not, in any way, involve the infringement of the secrecy of ballot at the election inasmuch as the elector who has subscribed the nomination paper of a person as a proposer or as a seconder is free to cast his vote in favour of any candidate and is not bound to vote for the person whose nomination paper he has subscribed as a proposer or seconder. The identity of the candidate in whose favour he has cast his vote is not to be disclosed.

In order to get over the requirements of Section 5B(1)(a) of the Act petitioner No. 1 has submitted that his nomination paper was subscribed by seven members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh as proposers and six members of the said Assembly as seconders. It has been pointed out that as per the statement of value of votes of elected members of the state Legislative Assembly issued as per the provisions of Article 55(2) of the Constitution the value of vote of a member of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh is 208 while the value of a member of the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh is 8. The submission is that the combined value of the votes of the seven members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh who had subscribed the nomination paper of petitioner No. 1 as proposers and six members who had subscribed as seconders is much more than the value of votes of 50 members of the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh and, therefore, the nomination paper of petition No. 1 must be treated as having been subscribed by 50 electors as proposers and seconders. Under Section 5B(1)(a) what is required is that the nomination paper just be subscribed by 50 electors as proposers and by 50 electors as subscribers. In relation to Presidential election the expression "elector" is defined in Section 2(d) of the Act to mean a member of the electoral college referred to in Article 54. Under Article 54 every elected member of the Legislative Assembly of the State is a member of the electoral college for election of the President. In other words, each member of the Legislative Assembly of a State is an elector under Section 2(d) of the Act. For the purpose of Section 5B(1)(a) of the Act the nomination paper must be subscribed by the requisite number of members of the State Legislative Assemblies or Parliament as proposers and seconders and the value of the votes of the member has no bearing on the said requirement laid down in Section 5B(1)(a) of the Act. For the reasons aforementioned, it must be held that since the nomination papers of the petitioners did not fulfil the mandatory requirements of Section 5B(1)(a) of the Act, and petitioner No. 2 also failed to comply with the requirements of Section 5B(2) of the Act, the petitioners were not duly nominated a candidate at the election and they cannot also claim to be duly nominated as candidate at the election and they cannot be regarded as "candidate" under Section 13(a) of the Act. The preliminary objection raised by respondent No. 1 that the petitioners cannot maintain the election petition must, therefore, be accepted and the election petition must be dismissed on this ground alone.

Before we conclude, we would like to advert to an aspect which cannot be ignored. Before filing this election petition, petitioner No. 1 had earlier filed three election petitions challenging the election of the returned candidates in the Presidential elections held in the years 1974, 1977 and 1982. All these election petitions were dismissed on the ground that petitioner had no *locus standi* to maintain the election petition. [See : *Charan Lal Sahu vs. Shri Fakruddin Ali Ahmed & Ors.* [supra]; *Charan Lal Sahu vs. Shri Neelam Sanjeeva Reddy*; and *Charan Lal Sahu vs. Giani Zail Singh* [supra].

Similarly petitioner No. 2 had earlier filed two election petitions challenging the election of the returned candidates in the Presidential elections held in the years 1987 and 1992. Both these election petitions were dismissed on the ground that petitioner had no locus standi to maintain the Election petition. [See : **Mithilesh Kumar vs. Sri R. Venkataraman & Ors.**, (1988) 1 SCR 525 and **Mithilesh Kumar Sinha. vs. Returning Officer for Presidential Election** (supra)] In **Charan Lal Sahu vs. Giani Zail Singh** [supra] this Court, while referring to the Election petition filed by petitioner No. 1, had observed

“It is regrettable that election petition challenging the election to the high office of the President of India should be filed in a fashion as cavalier as the one which characterizes these two petitions. The petitions have an extempore appearance and not even a second look, leave alone a second thought appears to have been given to the manner of drafting these petitions or to the contentions raised therein. In order to discourage the filing of such petitions, we would have been justified in passing a heavy order of costs against the two petitions. But that is likely to create a needless misconception that this Court, which has been constituted by the Act as the exclusive forum for deciding election petition whereby a Presidential or Vice-Presidential election is challenged, is loathe to entertain such petitions. It is of the essence of the functioning of a democracy that election to public offices must be open to the scrutiny of an independence tribunal. A heavy order of costs in these two petitions, howsoever justified on their own facts, should not result in nipping in the bud a well-founded claim on a future occasion. Therefore, we refrain from passing any order of costs and, instead, express our disapproval of the light-hearted and in different manner in which these two petitions are drafted and filed.” [17]

In **Mithilesh Kumar vs. Sri R. Venkataraman & Ors.** [supra], this Court had observed :

“While we expect every conscientious citizen eligible to file an election petition to question an election on the grounds prescribed by the Act, we do not wish that any petitioner should make use of this Court as a forum to file a petition without giving adequate thought to its contents and also to the provisions of law governing the case merely to seek some cheap publicity. We regret to say that seeing one's name in newspapers everyday has lately become the worst intoxicant and the number of people who have become victims of it is increasing day by day.” [537]

In **Mithilesh Kumar Sinha. vs. Returning Officer for Presidential Election** it was observed by this Court as follows :

“..... Experience has shown that the solemnity and significance attaching to such petition has been reduced to a force by the cavalier fashion in which resort is had to this remedy. The mere fact that the entire gamut of both these petitions is fully covered by several earlier decisions of this Court to some of which these very petitioners were parties shows that the existing provisions are inadequate to prevent such abuse of the process of law.” [p. 698]

We find that these observations have had no effect. This election petition which has been jointly filed by the two petitioners shows no improvement. It suffers from the same defects as the earlier petitions filed by the petitioners. It seems that the petitioners are observed with a desire that they should find a place in some Book of Records. They find the temptation to file an election petition after the Presidential election too difficult to resist. It is a matter of regret that petitioner No. 1, who happens to be an advocate himself, has been persisting in this past time knowing well that such conduct on his part amounts to an abuse of the process of law. This Court has so far refrained from imposing costs in the election petitions that were filed by the petitioners earlier. It is high time that the petitioners who have persisted in filing this petition in spite of the law laid down authoritatively by this Court in the earlier decisions are saddled with costs.

The Election petition is accordingly dismissed with costs. The costs are quantified at Rs. 10,000/- [Rupees ten thousand only]. The said amount of costs shall be deposited with the Supreme Court Legal Services Committee. It is also direct that no petition filed by either of the petitioners in person shall be entertained in this Court till the amount of costs imposed is paid.

[S. C. AGRAWAL]  
[G. N. RAY]  
[A. S. ANAND]  
[S. P. BHARUCHA]  
[S. RAJENDRA BABU]  
New Delhi,  
November, 24, 1997.  
[F. No. 14(11)/97-Leg.II]  
SUSHMA JAIN, Jt. Secy.